प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि दी गई है और उसमें से सीमावर्ती राज्यों के लिए कितनी धनराशि रखी गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) छठी योजना अवधि 1980–85 के दौरान मंडी, परवानू और धर्मशाला से शिमला तथा धर्मशाला से दिल्ली को एस० टी० डी० प्रदान करने की योजना है ।

(ख) जी नहीं । दुरूह पर्वतीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या, दूरी और आय की शर्तों के आधार पर निर्धारित विभागीय मानदण्डों के अनुसार डाकघर खोले जाते हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) डाकघरों के सम्बन्ध में सभी 16 डाक सर्किलों में उत्तरोत्तर रूप से विभागीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है । 1980–81 के दौरान, डाकघरों के भवन निर्माण हेतु 3.54 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिसमें से 83.56 लाख रुपये उन 4 डाक सर्किलों के लिए पृथक् तौर पर रखे गए हैं जो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के सीमावर्ती राज्यों की डाक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ।

टेलीफोन एक्सचेंजों के सम्बन्ध में, सीमित पूंजीगत साधनों को मद्देनजर रखते हुए, यह नीति अपनाई जाती है कि जहां तक संभव हो टेलीफोन एक्सचेंजों को किराये के आवास में ही रखा जाए । यद्यपि, बड़े स्वचल एक्सचेंजों, जिनके लिए विशेष रूप से योजित भवनों की आवश्यकता होती है के लिए सामान्य रूप से विभागीय भवनों का निर्माण किया जाता है ।

अन्य मामलों में विभागीय भवनों का निर्माण केवल उस समय किया जाता है जब किराये का उपर्युक्त आवास उपलब्ध नहीं होता ।

छठी योजना अवधि 1980–85 के दौरान, टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के निर्माण हेतु 105 करोड़ रुपये का आबंटन करने का प्रस्ताव है जिसमें से लगभग 16 करोड़ रुपये जम्मू एवं कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों हेतु आबंटित करने का प्रस्ताव है ।

Supply of rotten wheat in Kanpur

1989. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether attention of the Government has been invited to the news item pulbished in 'National Herald' of 5th August, 1980 "F.C.I. supplies rotten wheat in Kanpur"; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). Yes, Sir. The matter was investigated both by the Food Corporation of India authorities and the State Government. It was found that no damaged stocks were issued either through Public Distribution System or under Food for Work Programme in Kanpur.

The State Govenment issued a press release describing the news as 'incorrect' on the basis of the enquiry conducted in this connection.